



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

भ्रसाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 392] नई दिल्ली, बुहूपतिवार, सितम्बर 12, 1974/भाइ 21, 1896

No. 392] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 12, 1974/BHADRA 21, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संलग्न ही जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

### MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

#### ORDER

New Delhi, the 12th September 1974

S.O. 540(E)/15/IDRA/74.—Whereas by Order No. S.O. 298(E), dated the 18th May, 1974, published in the Gazette of India Extraordinary, in Part II Section 3 Sub-Section (ii) the Central Government appointed a body of persons for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the Aluminium Corporation of India Limited, Calcutta;

And whereas the said body was required to submit its report to the Central Government within a period of 15 days from the date of publication of the said Order in the Official Gazette;

And whereas the said body could not submit its report to the Central Government within the stipulated date;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the date for submission of the report by the said body, upto the 15th September, 1974.

[No. F.4/6/74-CUC]  
D. K. SAXENA, Jt. Secy

श्रीवैदिक विकास मंत्रालय

आदेश

मई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1974

**का० आ० 510 (भ) / 15/भ० ही भी आर ए/74.—यह केन्द्रीय सरकार ने, भारत के राजपत्र, प्रसाप्तारण, भाग 2, खंड 3 उप खंड (ii) में प्रकाशित आदेश सं० का० आ० 298(ई), तारीख 18 मई, 1974 द्वारा एन्युमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता की परिस्थितियों के बारे में समस्त और पूर्ण अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों का एक निकाय नियुक्त किया है :**

ग्रीर यतः उक्त निकाय से, उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट देने की घोषणा की गई थी ;

ग्रीर यतः इन्द्रुद्धित तारीख के भीतर उक्त निकाय अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को नहीं दे सका ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्तोग (विकास-और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की द्वारा 15 द्वारा प्रदत्त व्यक्तियों का प्रयोग करते हुये, उक्त निकाय द्वारा रिपोर्ट दिये जाने के लिये उस तारीख को 15 सितम्बर, 1974 तक विस्तारित करती है ।

[सं० फा० 4/6/74-सी यू सी]

डी० के० सेक्सेना, सचिवत सचिव ।